INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 12 | JANUARY - 2024

"रीवा जिले के नागरिकों के सामाजिक–आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास बैंकों की भूमिका : एक मूल्यांकन"

दिव्या पाण्डेय[1] , डॉ. संजय शंकर मिश्रा[2]
[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

बैंकिंग परिक्षेत्र में दूरगामी महत्व की प्रक्रिया जुलाई 1968 में हुयी थी, जब शासन स्तर पर एक सशक्त अध्यादेश जारी कर पच्चास करोड़ रूपये से अधिक की जमा राशि रखने वाले भारतीय अधिसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो वित्तीय प्रोत्साहन के क्षेत्र में बैंकों हेतु नये कलेवर में प्रवेश करने में द्योतक रहा, वास्तव में बैंकों के लिए उस प्रक्रिया की परिकाष्ठा रही जो वर्ष 1950 के दशक के मध्य में जीवन बीमा निगम एवं इम्पीरियल बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से प्रारम्भ हुयी थी। अधिनियम के प्रारम्भिक फेज में कहा गया था कि "बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विस्तृत लक्ष्य अर्थव्यवस्था की ऊँचाईयों को नियंत्रित करना तथा राष्ट्रीय नीतियों व उद्देश्यों के मद्देनजर अर्थव्यवस्था के विकास की अनिवार्यताओं को निरन्तर पूर्ण करना और उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना है।" ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निश्चित करना था कि ऋण लेने वालों में विशेषकर कृषक, लघु उद्यमों एवं स्वरोजगार करने वाले पेशेवरों के आकार तथा सामाजिक रूपरेखा की परवाह किये बगैर उनकी अनिवार्यताओं को पूर्ण करने पर विशेष बल प्रदान किया जाय। उन्हें नवीन एवं विकासशील साहसियों के उन्नयन को प्रोत्साहित करना था तथा राष्ट्र के अनेक हिस्सों के अविकसित क्षेत्रों में नवीन अवसरों का सृजन करना था, कुछ समय पश्चात् राष्ट्र में बनी अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत उन्हें आवंटित जिलों में ग्रामीण विकास बैंकों को सुविधायें मुहैया कराकर मार्गदर्शी की भूमिका का निर्वहन करना था। ऐसे बैंकों को समय–समय पर गरीबी उन्मूलन हेतु प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों की सफलता के ऋण मुहैया कराने की भी व्यवस्था करनी थी। रीवा जिले में ग्रामीण विकास बैंक इसी मार्ग का अनुशरण करके ग्रामीण अंचलों के आर्थिक व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

मुख्य शब्द– *ग्रामीण विकास बैंक, सामाजिक, आर्थिक विकास, ऋण, राष्ट्रीयकरण, अग्रणी बैंक, बैंक योजनाएँ एवं व्यावसायिक क्रियाकलाप।*

प्रस्तावना –

ग्रामीण विकास बैंकों में विशेषकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मध्यांचल बैंक, रीवा–सीधी ग्रामीण बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक इत्यादि प्रमुख रूप से संचालित हैं। जिनसे जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव रीवा जिले के विकासखण्डों में उपरोक्त ग्रामीण विकास बैंकों की शाखायें प्रमुख रूप से संचालित है, जिनके अनुत्पादक ऋण प्रबन्धन का वास्तविक आकलन करने हेतु शोधकर्ता ने

प्राथमिक स्तर पर जिले के विकासखण्डों में उपरोक्त ग्रामीण विकास बैंकों की शाखायें प्रमुख रूप से संचालित है। कृषि के क्षेत्र में नवीन अन्वेषण एवं आधुनिकता के प्रति कृषकों का जवाब संतोषजनक नहीं रहा है। ग्रामीण विकास की इस कमी का मुख्य कारण यह रहा है कि आज भी भारतीय वर्ष में निचले स्तर पर वित्तीय संसाधनों की कमी है। यह अनुभव किया गया है कि नवीन संसाधनों से सुसज्जित कृषक इस विकास योजना के लाभ को प्राप्त करने में सक्षम है, किन्तु वित्तीय कमी की वजह से निर्धन व गरीब कृषक इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस तरह वित्त की अभाव नवीनीकरण के द्वारा बदलाव लाने में बहुत बड़ी बाधा है। भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन किसान, ग्रामीण कारीगर एवं ग्रामीण आबादी के दूसरे निर्धन व कमजोर वर्ग पूंजी के कमी के लाभ से वंचित होकर अपना जीवन जी रहे हैं अतः ग्रामीण विकास में उनकी सहभागिता उपेक्षित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख ध्येय भारत का ग्रामीण विकास और कृषि विकास करना है। ग्रामीण विकास और कृषि विकास दोनों एक–दूसरे के पूरक है।

क्षेत्र के विकास में बैंकों की एक विशेष भूमिका होने के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने स्थापना काल से वर्तमान समय तक उन्नति के नवीन आयाम स्थापित किया है। अपनी स्थापना से अब तक की अल्प समयावधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा राष्ट्र के अर्द्धनगरीय और ग्रामीण भागों में वित्तीय सुविधाओं को अधिक से अधिक मुहैया करवाये जाने की दृष्टिकोण से अपनीशाखाओं को तीव्र गति से विस्तार किया है। वर्तमान समय में समस्त राष्ट्र में 196 ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो चुकी है। भारतीय बैंकिंग जगत में व्यापक आर्थिक सुधारों का क्रम 1991 में शुरू किया गया। इसे परिप्रेक्ष्य में वित्तीय सुधार समिति का अभिमत था कि इन सुधारों के क्रियान्वयन से बैंकों की वित्तीय परिस्थिति में पारदर्शिता आयेगा। इस क्रम में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता के मापदण्डों को लागू की गयी। अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के माध्यम से प्रदत्त ऋणों पर ब्याज दरों की अविनियमन की धारण को मूर्त स्वरूप किया। इससे भारतीय बैंकिंग संसार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण और बैंकिंग के नवीन युग का सूत्रपात हुआ और वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुआ जिससे ग्रामीण वित्त के नवीन अवसर और चुनौतियां भी उभरी है।

वित्तीय और विकासात्मक गतिविधि और गतिशील प्रक्रिया है जिनका कार्य किसी युग में समाप्त नहीं होता है। परिवर्तन होता सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण, नव विकास और साख आवश्यकताओं के मध्य अंकुरित करके संवर्द्धन के नवीन आयाम सृजित करता रहता है। परिवर्तित हुयी परिस्थितियों के अनुकूल ग्रामीण आवश्यकताओं में भी बदलाव आती रहती हैं। इन बदलाव जन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आर्थिक भारतीय नव बैंकिंग के क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण गतिविधियों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर होता है। रीवा जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित ग्रामीण विकास बैंकों के अनुत्पादक ऋण के प्रबन्ध से संबंधित शोध अध्ययन को निष्पादित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, जिन्हें केन्द्र में रखते हुए शोधार्थी ने उद्देश्यों से संबंधित मौलिक समंकों का संग्रहण साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण के समय किया है, ताकि उनकी वास्तविकता का आकलन किया जा सके।

उद्देश्य –

शोध समस्या एक व्यापक एवं सार्वभौमिक कथन होता है इसका संबंध एक बड़े क्षेत्र से होता है इसमें कई कारण एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह आपस में जटिलताओं से जुड़े रहते हैं इसलिए सभी का एक साथ अध्ययन संभव नहीं होता है। अतएव प्रत्येक शोध कार्य का भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, इन उद्देश्यों को लेकर ही शोध कार्य संचालित किया जाता है। शोधार्थी ने अपनी शोध समस्या की सम्पूर्ण जानकारी एवं सभी पक्षों का अध्ययन करने के लिये निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण कर उनके समुचित निदान ढूंढने का इस शोध अध्ययन के माध्यम से अकादमिक प्रयास किया गया है जो इस प्रकार है–

- रीवा जिले के ग्रामीणों में आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास बैंकों का महत्व।
- ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा रीवा जिले के ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान का अध्ययन करना।
- शोध क्षेत्र के ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जिले के सामाजिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों को मूल्यांकित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्र में रखकर शोध आलेख को प्रस्तुत करने का अकादमिक प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है।

परिकल्पना –

परिकल्पना से संबंधित उपरोक्त पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात् शोधकर्ता ने चयनित शोध आलेख से संबंधित कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया है, जो क्रमशः निम्नानुसार है–

- शोध क्षेत्र के ग्रामीणों के समाजार्थिक विकास में ग्रामीण विकास बैंकों का सर्वोच्च योगदान है।
- शोध क्षेत्र में ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नागरिकों को उद्यम स्थापित करने के लिये साख सुविधा प्रदान किये जाने का मूल्यांकन करना।
- ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा ग्रामीण अंचल में बसे हुए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को ही निरन्तर साख (ऋण) उपलब्ध कराता है।

शोध आलेख से संबंधित उपरोक्त सभी परिकल्पनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि –

प्रस्तावित शोध आलेख का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 09 विकासखण्ड हुजूर, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर, जवा, हनुमना, गंगेव, त्योंथर, नईगढ़ी एवं मऊगंज हैं। अतः जिला अन्तर्गत स्थित सभी विकासखण्डों को अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण विकास बैंकों में अनुत्पादक ऋण प्रबंधन का अध्ययन करने के लिये न्यादर्श के रूप में चयनित ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारी, हितग्राही, सरपंचों व अधिकारियों एवं प्रत्येक विकासखण्डों से कुल 540 हितग्राहियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से कर साक्षात्कार के समय प्रश्नावली का उपयोग कर प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित किया गया है।

विश्लेषण –

रीवा जिले के विकासखण्डों में संचालित ग्रामीण विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का सामाजिक विकास हो रहा है या नहीं से संबंधित मौलिक तथ्यों को सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम से संग्रहित किया गया है। इन संकलित मौलिक आंकड़ों से वास्तविकता का मूल्यांकन करने के लिए इन्हें सारणी क्रमांक 01 में वर्गीकरण के साथ प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जो इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक 01
ऋणों से हितग्राहियों का सामाजिक विकास होने का विवरण

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सामाजिक विकास होता है	397	73.52
2.	सामाजिक विकास नहीं होता है	143	26.48
योग		540	100.00

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

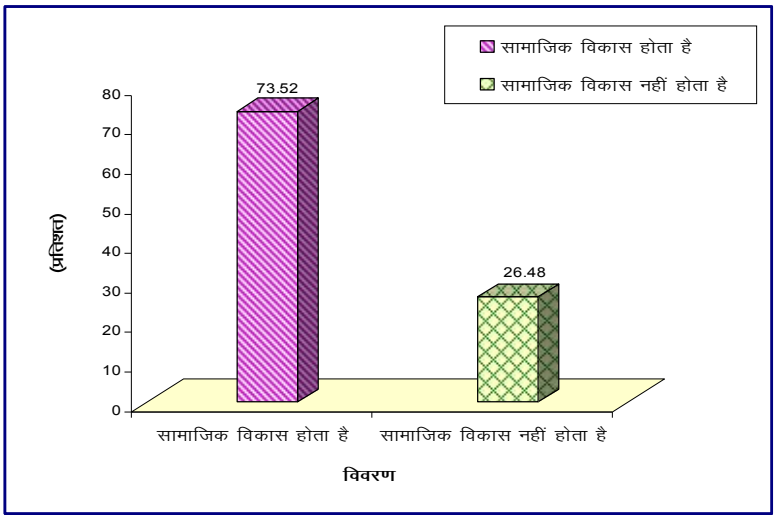

आरेख क्रमांक 01 : ऋणों से हितग्राहियों का सामाजिक विकास होने का विवरण।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 एवं आरेख को देखने से प्रतीत होता है कि जिले के ग्रामीण विकास बेंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक विकास होने व न होने से संबंधित है जिसके लिए सर्वेक्षित कुल 540 व्यक्तियों में से 397 लोगों ने बतलाया कि इन बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का आर्थिक विकास होने के साथ–साथ सामाजिक विकास भी हो रहा है जिनका प्रतिशत 73.52 है, जबकि वहीं 143 लोगों ने बतलाया कि इन ऋणों से लोगों का सामाजिक विकास नहीं होता है जिनका प्रतिशत 26.48 है।

जिले के ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों की सुविधाओं से हितग्राहियों के आर्थिक विकास सम्भव हो रहे है या नहीं, से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों को सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित करते समय साक्षात्कार प्रश्नावली का प्रयोग कर संग्रहित किया गया है, इन संकलित प्राथमिक आंकड़ों से वास्तविक प्रतिफल प्राप्त करने हेतु उन्हें सारणी क्रमांक 02 में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक विवेचन का कार्य किया गया है जो इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक 02
ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणों से हितग्राहियों के आर्थिक विकास

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हितग्राहियों का आर्थिक विकास सम्भव हो रहा है	493	91.30
2.	हितग्राहियों का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो रहा है	41	7.59
3.	कुछ कह नहीं सकते	06	1.11
योग		540	100.00

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

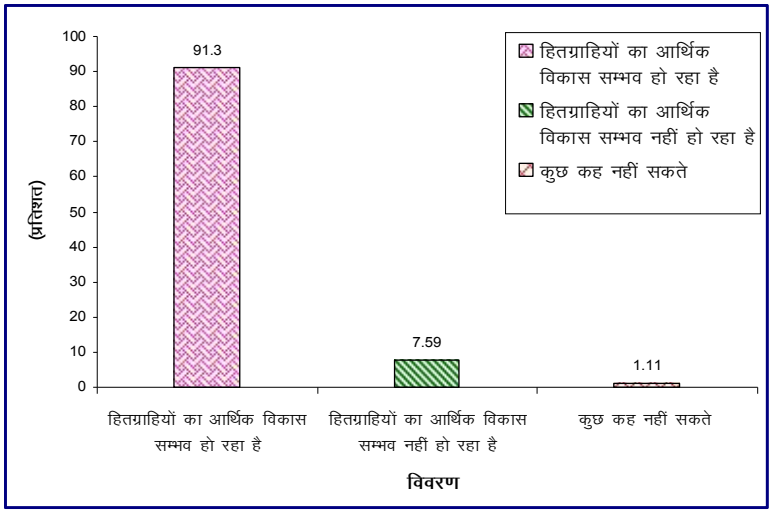

आरेख क्रमांक 02 : ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणों से हितग्राहियों के आर्थिक विकास।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 02 एवं आरेख को देखने से प्रतीत होता है कि यह ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणों से हितग्राहियों के आर्थिक विकास से संबंधित है। शोधकर्ता द्वारा जिले से चयन किये गये कुल 540 उत्तरदाताओं में 493 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि हितग्राहियों का आर्थिक विकास सम्भव हो रहा है जिनका प्रतिशत 91.30 है इसी प्रकार 41 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि हितग्राहियों का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो रहा है जिनका प्रतिशत 7.59 है। इसी प्रकार 06 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि कुछ कह नहीं सकते जिनका प्रतिशत 1.11 है।

रीवा जिले के नगरी/ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास को वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग प्राप्त होने से संबंधित प्राथमिक समंकों को सर्वेक्षण के माध्यम से प्रश्नावली का उपयोग कर संकलित किया गया है और इन संग्रहित आंकड़ों की सत्यता का परीक्षण करने हेतु सारणी क्रमांक 03 में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक व्याख्या की गई है जो इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक 03
बैंकों के ऋणों से ग्रामीण अंचलों के लोगों को वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग प्राप्त हो रहा है	485	89.81
2.	वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है	31	5.74
3.	कुछ कह नहीं सकते	24	4.44
योग		540	100.00

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

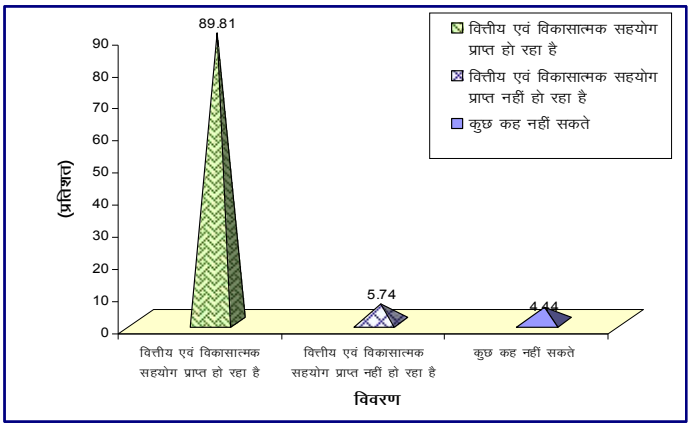

आरेख क्रमांक 03 : बैंकों के ऋणों से ग्रामीण अंचलों के लोगों को वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग।

उक्त सारणी क्रमांक 03 एवं आरेख को देखने से प्रतीत होता है कि यह बैंकों के ऋणों से ग्रामीण अंचलों के लोगों को वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग से संबंधित है। शोधकर्ता द्वारा जिले से चयन किये गये कुल 540 उत्तरदाताओं में 485 उत्तरदाताओं ने अपना अभिमत दिया कि वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग प्राप्त हो रहा है जिनका प्रतिशत 89.81 है। इसी प्रकार 31 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है जिनका प्रतिशत 5.74 है और 24 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि कुछ कह नहीं सकते जिनका प्रतिशत 4.44 है।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः रूप में यह कहा जा सकता है कि जिले के विकासखण्डों में संचालित ग्रामीण विकास बैंको से लोग ऋण की राशि प्राप्त कर जिले के नागरिक अपना सामाजिक विकास करने की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी सामाजिक आवरण धीरे–धीरे नगरों का रूप लेने लगा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास त्वरित गति से होने के कारण ग्रामीण परिवेश भी आधुनिकता के दौर के अनुसार विकसित होने लगा है। जिले में ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणों से हितग्राहियों के आर्थिक विकास सम्भव हो रहा है। जिससे उनके रहन–सहन, खान–पान एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे रीवा जिले की समाजार्थिक स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले की ग्रामीण विकास बैंकों से ऋण की सुविधा प्राप्त कर हितग्राही वर्ग अपना एवं अपने परिवार का विकास करने के साथ–साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी सक्षम हो रहे हैं जिससे जिले की बेरोजगारी में काफी कमी आयी है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. गौतम, डॉ. ए.के. एवं खातून, फरीदा – जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय प्रबंधन एवं कृषि विकास में योगदान का मूल्यांकन, इंटरनेशनल जनरल ऑफ रिव्यू एण्ड रिसर्च इन सोशल साइंस, वर्ष 2018
2. शर्मा, टी.आर. – आर्थिक नियोजन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2015
3. रूद्र, पी.के.एम. – भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चांद एवं कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, वर्ष 2001
4. देसाई, भैरव एच. – राज्य भूमि विकास बैंक का वित्तीय सम्पादन : एक अध्ययन, कोआपरेटिव प्रास्पेक्टिव, वर्ष 2010
5. खन्ना, एम.एस. – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्यवसाय का विकास, योजना वर्ष 2015
6. ग्रामीण विकास बैंक की रिपोर्ट, केन्द्र सरकार, वर्ष 2019
7. मेहता, डॉ. जे.के. – आधुनिक भारत की आर्थिक समस्याएं, हिमालय पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2008